

## उचति एकोमोडेशन का सदिधांत

### प्रलिमिंस के लयि:

अंतर्राष्ट्रीय शर्म संगठन (ILO), सर्वोच्च न्यायालय, हजिाब, मौलकि अधकिार, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधति मामले, दवियांगजन अधकिार अधनियिम, 2016।

### मेन्स के लयि:

उचति आवास' का सदिधांत, मौलकि अधकिार, न्यायपालकिा, सरकारी नीतयिाँ और हस्तक्षेप, महिलाओं से संबंधति मुद्दे, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधति मामले।

## चर्चा में क्योँ?

हाल ही में हजिाब वविाद के संदर्भ में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के परपित्त्र के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को केवल ज़रूरी नरिंधारति ड्रेस/वेशभूषा पहननी चाहयि।

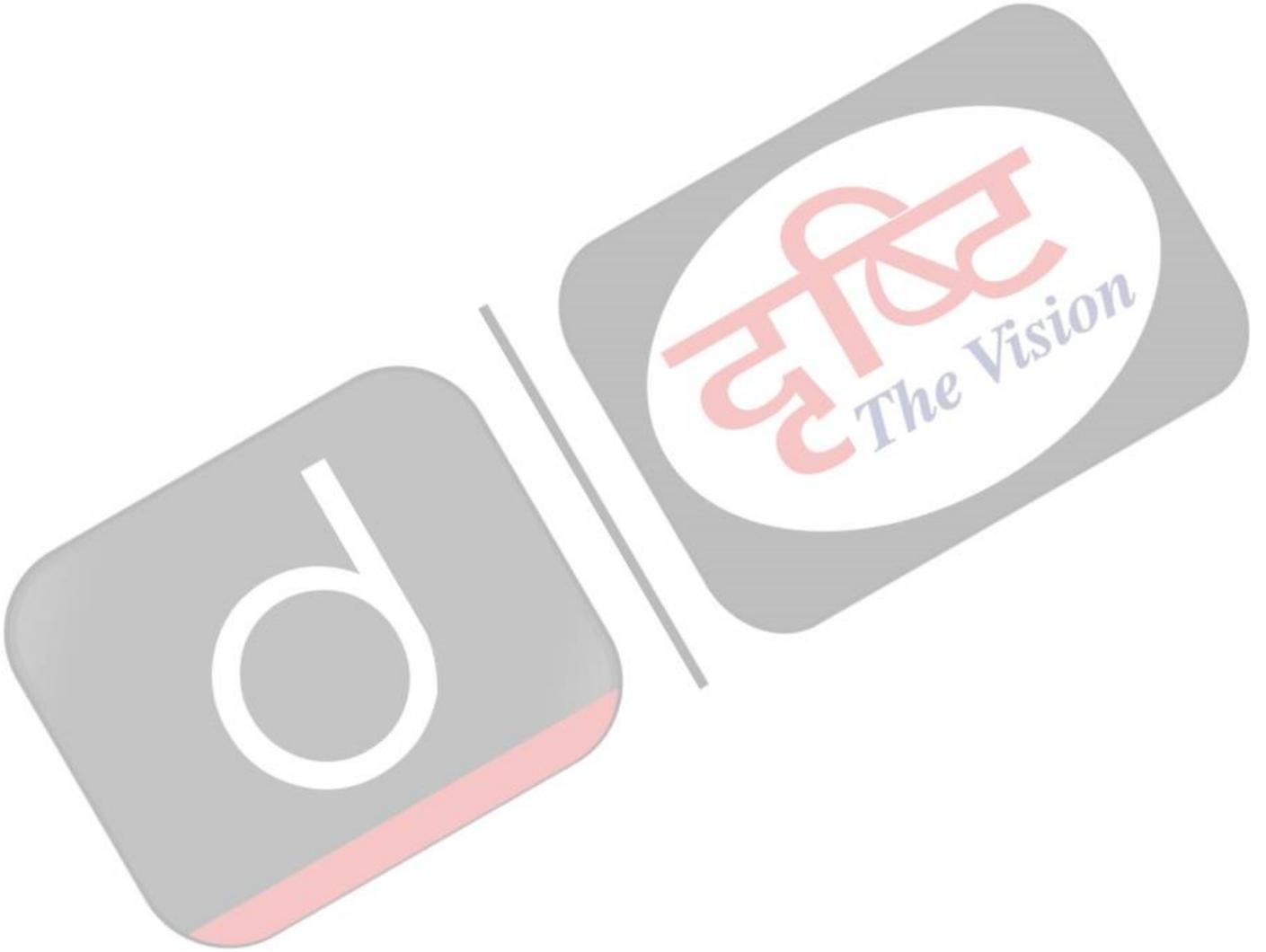
- इस नरिणय ने शैक्षणिक संस्थानों में हजिाब पहनने वाले छात्रों के प्रवेश पर प्रतबिंध को प्रभावी ढंग से बरकरार रखा।
- न्यायालय ने मुस्लिम लड़कयिों को 'उचति आवास' के सदिधांत पर आधारति स्कार्फ/हजिाब पहनने की अनुमतदिने के समर्थन में दयि गए एक तर्क को खारजि कर दयि।

## प्रमुख बदि

### 'उचति एकोमोडेशन' का सदिधांत:

- **उचति एकोमोडेशन' के सदिधांत के बारे में:** 'उचति एकोमोडेशन' एक सदिधांत है जो समानता को बढ़ावा देता है, सकारात्मक अधकिार प्रदान करने में सक्षम बनाता है और दवियांग, स्वास्थय की स्थति या व्यक्तगित वशिवास के आधार पर भेदभाव को रोकता है।
  - इसका उपयोग मुख्य रूप से दवियांगता अधकिार क्षेत्र (Disability Rights Sector) में होता है।
  - यह दवियांग व्यक्तयिों को समाज में उनकी पूरण और प्रभावी भागीदारी को सुवधाजनक बनाने के लयि अतरिकित सहायता प्रदान करने हेतु राज्य एवं नजिी संस्थानों के सकारात्मक दायतिव को दर्शाता है।
  - यदि विकिलांग व्यक्त को कोई अतरिकित समर्थन नहीं दयिा जाता है, तो संवैधानकि रूप से गारंटीकृत **समानता के मौलकि अधकिार** (अनुच्छेद-14), **छह स्वतंत्रताओं** (अनुच्छेद-19) और **जीवन के अधकिार** (अनुच्छेद-21) का महत्त्व नहीं रह जायगा।
- **विकिलांग लोगों के अधकिारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुच्छेद-2 (UNCRPD):** यह आवश्यक एवं उचति समायोजन है, जसिके मुताबकि विकिलांग व्यक्तयिों पर कसिी भी प्रकार का असंगत या अनुचति बोझ न डाला जाए, ताकयिे अन्य लोगों की तरह अपने सभी मानवाधकिारों का लाभ ले सकें।

॥



## अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) केस स्टडी:

- ILO वर्ष 2016 में कार्यस्थल समायोजन के माध्यम से विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिये एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका लेकर आया था।
- कार्यस्थल आवास की आवश्यकता विभिन्न स्थितियों में उत्पन्न हो सकती है, लेकिन इसके तहत श्रमिकों की चार श्रेणियों को चुना गया था:
  - वकिलांग श्रमिक।
  - एचआईवी और एड्स से पीड़ित श्रमिक।
  - गर्भवती श्रमिक और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों वाले लोग।
  - एक विशेष धर्म या विचारधारा के लोग।
- श्रमिकों की इन श्रेणियों को काम के दौरान विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इनके परिणामस्वरूप या तो रोज़गार का नुकसान हो सकता है या रोज़गार तक पहुँच में कमी हो सकती है।
- उचित आवास का प्रावधान इन बाधाओं को दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और इस प्रकार कार्यस्थल पर समानता, विविधता और समावेश में अधिक से अधिक योगदान देता है।
- एक संशोधित कार्य वातावरण, संकषित या चौका देने वाली कार्यावधि, पर्यवेक्षी कर्मचारियों से अतिरिक्त सहायता तथा कम कार्य प्रतबिद्धताएँ ऐसे तरीके हैं जिनसे आवास बनाया जा सकता है।

## वर्षों के प्रश्न

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय 138 और 182 संबंधित हैं: (2018)

- (a) बाल श्रम
- (b) वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषिपद्धतियों का अनुकूलन
- (c) खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का वनियमन
- (d) कार्यस्थल पर लैंगिक समानता

उत्तर: (a)

## भारत में इससे संबंधित कानून:

- भारत में [द्वियांगजन अधिकार अधिनियम 2016](#) 'उचित आवास' को "आवश्यक और उचित संशोधन एवं समायोजन, किसी विशेष मामले में एक असमान या अनुचित बोझ डाले बिना, वकिलांग व्यक्तियों के लिये दूसरों के साथ समान रूप से अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने" आदि के रूप में परिभाषित करता है।
  - धारा 2(h) में 'भेदभाव' की परिभाषा में 'उचित आवास से इनकार' शामिल है।
- [जीजा घोष और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य \(2016\)](#): [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने माना कि समानता का मतलब न केवल भेदभाव को रोकना है, बल्कि समाज में व्यवस्थापित भेदभाव से पीड़ित समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना भी है।
  - कठोर शब्दों में इसका अर्थ "सकारात्मक अधिकारों, सकारात्मक कार्रवाई और उचित समायोजन की धारणा को अपनाने से है।"
- [वकिश कुमार बनाम यूपीएससी \(2021\)](#): न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बैचमार्क वकिलांगता, जो कि 40% की सीमा तक निर्दिष्ट एक वकिलांगता है, द्वियांगों के लिये केवल रोज़गार में विशेष आरक्षण से संबंधित है, लेकिन अन्य प्रकार की एकोमोडेशन के लिये प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है।
  - यह भी कहा गया कि भेदभाव के संबंध में उचित एकोमोडेशन प्रदान करने में विफलताएँ देखने को मिली हैं।

## वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: भारत लाखों द्वियांग व्यक्तियों का घर है। उनके लिये कानून के अंतर्गत क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापति करने के लिये भूमिका अधिमिन्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टू

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/principle-of-reasonable-accommodation>

